



आर्थिक पूंजी ढाँचा एवं RBI द्वारा लाभांश अंतरण

प्रलिस के लयः

[भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#), [आर्थिक पूंजी ढाँचा \(ECF\)](#), [आकसमकऱ जोखमऱ बफर \(CRB\)](#), [बमऱल जालान समतऱ](#), [तरलता समायोजन सुवधऱ \(LAF\)](#), [खुले बाज़ार परचऱलन \(OMOs\)](#), [मौदरकऱ नीतऱ](#), [सकल घरेलू उतपाद \(GDP\)](#)

मेन्स के लयः

आर्थिक पूंजी ढाँचा (ECF), RBI दवारा सरकार को अधशऱष अंतरण, संबंघतऱ प्रऱवधऱन एवं महत्त्व ।

[सुरोतः इंडयऱन ँकसपरस](#)

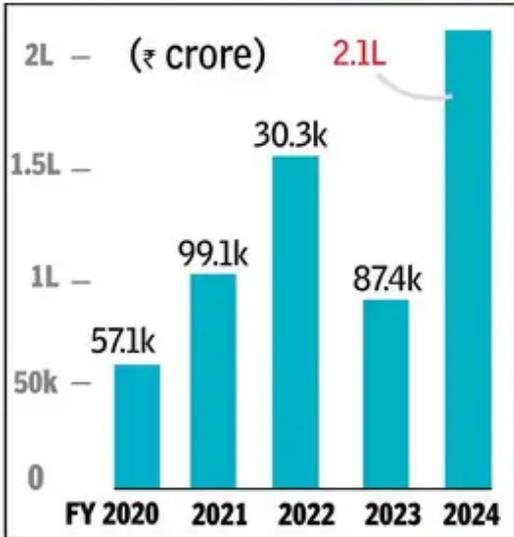
चरचा में कयों?

[भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#) के केंद्रीय नदऱशक मंडल ने जोखमऱ प्रऱवधऱन के सऱथ केंद्रीय बैंक से सरकार को कयऱ जाने ऱले लाभांश (अधशऱष) वतऱरण के नरऱधारण के कऱम में [आर्थिक पूंजी ढाँचे \(ECF\)](#) कऱ आकलन कयऱ ।

आर्थिक पूंजी ढाँचा (ECF) कयऱ है?

- **परचयः** यह RBI दवारा जोखमऱ प्रऱवधऱनों के उचतऱ सतर तथऱ अधशऱष (लाभ) को नरऱधारतऱ करने के कऱम में अपनऱयऱ गयऱ ँक संरचतऱ तंत्र है । इस अधशऱष को **RBI अधनऱयऱम, 1934 कऱ धऱरऱ 47** के तहत **भऱरत सरकार** को अंतरतऱ कयऱ जऱ सकतऱ है ।
 - इसकऱ सफऱरशऱ **बमऱल जालान (RBI के पूरव गवरनर) समतऱ (वर्ष 2018)** दवऱरऱ कऱ गई थी और इसे औपचऱरकऱ रूप से वर्ष 2019 में अपनऱयऱ गयऱ थऱ ।
- **उददेश्यः** इसकऱ उददेश्य **मौदरकऱ एवं वतऱतीय स्थरऱतऱ** के कऱम में **परयऱप्त वतऱतीय बफर** बनाए रखने के सऱथ **ववऱकपूरण अधशऱष वतऱरण** के बीच संतुलन बनऱनऱ है ।
 - यह **(CRB) RBI कऱ बैलेंस शीट कऱ 5.5% से 6.5%** तक कऱ वतऱतीय सुरकषऱ संजऱल है जसऱसे संकट के समय ःणदऱतऱ के रूप में कऱर्य करने कऱ इसकऱ स्थरऱतऱ और कषमतऱ सुनशऱचतऱ होतऱ है ।
 - यह RBI को मुदरऱ अस्थरऱतऱ तथऱ आर्थऱक वतऱतीय संकट जैसे **अपरतयऱशतऱ उतऱर-चढऱव के प्रतऱवतऱतीय सुरकषऱ** के रूप में **आकसमकऱ जोखमऱ बफर (CRB)** बनाए रखने में सकषम बनऱतऱ है ।
- **संशोधतऱ ECF (बमऱल जालान समतऱ कऱ सफऱरशऱ, 2019):**
 - **वऱसतवकऱ इक्वऱटी (आकसमकऱ नधऱ-CF):** आकसमकऱ नधऱ, **अपरतयऱशतऱ कषतऱ के वरऱदध बफर** के रूप में भूमकऱ नभऱतऱ है और इसे **RBI कऱ बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5%** के बीच बनाए रखऱ जऱतऱ है ।
 - इस सीमऱ से अतरऱकऱतऱ रऱशऱ सरकार को अंतरतऱ कर देऱ जऱतऱ है । RBI के केंद्रीय बोरड दवऱरऱ इस लकष्य को **5.5% कऱ नमऱनतम सीमऱ** के रूप में नरऱधारतऱ कयऱ गयऱ है ।
 - **आर्थऱक पूंजी (पूंजी और सऱमऱन्य जोखमऱ खऱतऱ- CGRA):** CGRA में **RBI कऱ पूंजी, भंडऱर, जोखमऱ प्रऱवधऱन एवं वनऱमऱय दरों, स्वर्ण कऱमतों और बयऱज दरों** में उतऱर-चढऱव से उतपन्न पुनरमूलयऱंकन शेष शऱमलऱ हैं ।
 - इसे **बैलेंस शीट आकऱर के 20.8% से 25.4% के बीच बनाए रखऱ जऱनऱ है** तथऱ कसऱी भी अतरऱकऱतऱ रऱशऱ को केंद्र को हसतऱंतरतऱ कयऱ जऱ सकतऱ है ।
- **समऱकषऱ तंत्रः** समतऱ कऱ सफऱरशऱ के अनुसार, **उभरतऱ आर्थऱक स्थतऱतऱयऱं और जोखमऱं के समायोजन** के लयऱ ECF कऱ प्रतयेक 5 वर्ष में समऱकषऱ कऱ जऱतऱ है तथऱ नवऱनतम समऱकषऱ अगस्त 2024 में कऱ गई थी ।
- **लाभांश हसतऱंतरण में रुझऱनः** RBI दवऱरऱ **सरकार को लाभांश हसतऱंतरण वतऱतऱ वर्ष 2021-22 में 30,307 करोड रुपए से बढकर वतऱतऱ वर्ष 2024-25 में अनुमऱनतऱ 2.5-3 लऱख करोड रुपए** हो गयऱ है ।
 - इस तीव्र वृद्धकऱ श्रेय **डॉलर कऱ बकऱरी से होने ऱली मज़बूत ऱय, स्वर्ण कऱ बढतऱ कऱमतों और सरकऱरी प्रतऱभूतऱयऱं में वृद्धकऱ** दयऱ जऱतऱ है ।
 - इस उच्च लाभांश से **रऱजकोषीय घऱटे को प्रबंधतऱ करने, बैंकगऱ तरलतऱ को बढऱने और संभवऱतऱ रूप से अल्पकऱलकऱ बयऱज दरों को ऱसऱन बनऱने में सऱहऱयतऱ मऱलऱगी** ।

RBI'S PAST DIVIDENDS TO GOVT



➤ Central board of directors reviewed the economic capital framework at its meeting on Thursday

➤ Economists expect RBI to transfer a dividend of ₹2.5-2.75 lakh crore to govt

➤ RBI gov Sanjay Malhotra had flagged ongoing review in Feb following the MPC meeting

RBI के अधिशेष हस्तांतरण को नयित्तरति करने वाले प्रावधान क्या हैं?

- **RBI अधिनियम, 1934:** RBI अधिनियम की धारा 47 में यह प्रावधान है कि आकस्मकता नधि (CF) और आस्त विकास नधि (ADF) के लिये प्रावधान करने के बाद RBI का नविल लाभ केंद्र सरकार को हस्तांतरति कयिा जाना चाहयिे।
 - धारा 48 RBI को अपनी आय पर आयकर या सुपर टैक्स का भुगतान करने से छूट देती है, जसिसे अधशिष को राजकोष में सीधे स्थानांतरति कयिा जा सके।
- **समति की सफिरशि:** ऐतहिासकि रूप से, RBI अपने आंतरकि भंडार को मज़बूत करने के लयिे अपने लाभ का एक बडा सुरक्षति रखता है।
 - पछिले कुछ वर्षों में, कई वशिषज्ज समतियिों ने RBI के पूंजी बफर की पर्याप्तता और हस्तांतरति कयिे जाने वाले अधशिष की मात्रा की जाँच की है:
 - वी. सुबरहमण्यम समति (1997)
 - उषा थोराट समति (2004)
 - वाई.एच. मालेगाम समति (2013) ने वविकपूर्ण भंडार बनाए रखते हुए सरकार को अधिक हस्तांतरण की सफिरशि की।
 - बमिल जालान समति (2018) ने राजकोषीय आवश्यकताओं के साथ जोखमि प्रावधान को संतुलति करते हुए संशोधति आर्थकि पूंजी ढाँचा (ECF) पेश कयिा।
 - इन सफिरशिों, वशिषकर मालेगाम और जालान समतियिों की सफिरशिों के बाद, RBI ने सरकार को अपने अधशिष हस्तांतरण में उत्तरोत्तर वृद्धि की है, जसिसे समष्टि आर्थकि स्थरिता और सार्वजनकि व्यय के लयिे राजकोषीय स्थान उपलब्ध हुआ है।

RBI के प्रमुख आय एवं व्यय शीर्ष क्या हैं?

आय का स्रोत	
	<ul style="list-style-type: none"> • रुपे परतभूतयिों पर ब्याज: रुपे-मूल्यवर्गति सरकारी परतभूतयिों को धारण करने से अर्जति आय, उनकी बकिरी या मोचन पर लाभ या हानि के साथ-साथ मूल्यहरास और परशिोधन व्यय के लयिे समायोजति। <p>तरलता समायोजन सुवधि (LAF) और सीमांत स्थायी सुवधि (MSF) से ब्याज: LAF और MSF तंत्र के तहत परचालन के माध्यम से अर्जति शुद्ध ब्याज।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऋण और अग्रमि पर ब्याज: केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, वतितीय संस्थानों और RBI के कर्मचारयिों को दयिे गए ऋणों के ब्याज से आय। • वदिशी मुद्रा परसिंपत्तयिों से ब्याज: RBI द्वारा धारति वदिशी

	मुद्रा-मूल्यवान परसिंपत्तियों पर ब्याज से आय ।
व्यय	<p>ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)</p> <p>जोखमि प्रावधान: RBI 2 प्रमुख जोखमि नधि रखता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आकस्मिक नधि (CF): परतभित्तियों के मूल्य में मूल्यहरास और मौद्रिक नीतिपरिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले जोखमि जैसी अप्रत्याशति आकस्मिकताओं को कवर करने के लिये अलग से रखी गई नधि । • परसिंपत्त विकास नधि (ADF): सहायक कंपनियों और संबद्ध संस्थानों में नविश के साथ-साथ आंतरिक पूंजीगत व्यय के लिये आवंटित राशि । <ul style="list-style-type: none"> • मुद्रा मुद्रण लागत: बैंक नोटों की छपाई से संबंधित व्यय । • एजेंसी शुल्क: बैंकों, प्राथमिक डीलरों और मुद्रा वितरण एवं सरकारी परतभित्तियों के परिचालन में शामिल अन्य एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन । • परिचालन व्यय: RBI के कर्मचारियों के वेतन, लाभ और अन्य संबंधित लागतें । • जमा और ऋण पर दिया गया ब्याज: ग्राहकों द्वारा जमा की गई धनराशि, अंतर-बैंक ऋण, केंद्रीय बैंक की सुविधाओं या बॉण्ड जैसे ऋण साधनों पर ब्याज भुगतान के रूप में बैंक द्वारा किया गया व्यय ।
आधिक्य	<ul style="list-style-type: none"> • कुल आय (आय के स्रोत) में से कुल व्यय (खर्च) को घटाने पर प्राप्त शुद्ध आय । • वित्तीय स्थिरता और आपात स्थितियों के लिये आरक्षण नधि और आकस्मिक प्रावधान ।

RBI द्वारा सरकार को अधशेष हस्तांतरण का क्या महत्त्व है?

- **राजकोषीय घाटे को कम करना:** गैर-कर राजस्व में वृद्धिकरके वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% के [राजकोषीय घाटे](#) के लक्ष्य को पूरा करने में सरकार की सहायता करता है ।
- **राजस्व सृजन में वृद्धि:** यह एक प्रमुख [गैर-कर राजस्व](#) स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तथा आर्थिक विकास को समर्थन मलता है ।
- **सरकारी ऋण में कमी:** सकल ऋण में 1 ट्रिलियन रुपए तक की कमी हो सकती है, जिससे पूंजीगत परियोजनाओं के लिये धनराशि उपलब्ध हो सकेगी ।
- **ऋण लेने की लागत में कमी:** ऋण लेने की कम ज़रूरतें **G-Sec परतफिल** को कम कर सकती हैं, जिससे सरकार का ऋण सेवा भार कम हो सकता है ।
- **ब्याज दरों पर नियंत्रण:** गरिती हुई [साँवरेन यीलड](#) व्यापक रूप से बाज़ार दरों को प्रभावित करती है, जिससे व्यवसायों और परिवारों के लिये ऋण लेना सस्ता हो जाता है ।

नषिकर्ष:

आर्थिक पूंजी ढाँचा **RBI** की स्वायत्तता और सरकार की राजकोषीय आवश्यकताओं के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है । स्पष्ट रूप से **जोखमि बफर** और **अधशेष हस्तांतरण नियम** निर्धारित करके, यह वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय वविक को बढ़ावा देता है । यह ढाँचा **सतत् आर्थिक विकास** का समर्थन करता है और **व्यापक रूप से आर्थिक अनुकूलता** को मज़बूत करता है ।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ECF) क्या है और यह भारतीय रज़िर्व बैंक की स्वायत्तता एवं सरकार की राजकोषीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन किस प्रकार बनाए रखता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस

प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह RBI की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है।
2. यह RBI के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है जिसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक वस्तुवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुवर्धा दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)